उत्तराखंड को खनन सुधारों पर 100 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि

देहरादून, सुनील तलवाड़ (पंजाब केसरी): उत्तराखंड खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट सुधारों के लिए केंद्र सरकार से एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाब रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में किए गए निरंतर सुधार और पारदर्शी नीतियों के चलते केंद्रीय खन मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।

इससे पहले अक्टूबर 2025 में राज्य को एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त होने पर पहले ही 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी थी। इस तरह, उत्तराखंड को खनन सुधारों के लिए कुल 200 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी है। केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि राज्य ने खनन क्षेत्र से संबंधित अधिकांश सुधारात्मक कार्यवाहियों को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया है।

● उत्तराखंड खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट सुधारों के लिए केंद्र सरकार से एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाब रहा

विशेष रूप से माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स के सात प्रमुख मानकों में से छह को सफलतापूर्वक पूरा करने के कारण उत्तराखंड ने खनन सुधारों में देश में नंबर-1 स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए कई नीतियां लागू की हैं।

इन सुधारों के चलते सरकारी खजाने को मजबूती मिली है, स्थानीय लोगों और कारोबारियों को रोजगार और आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, और निर्माण सामग्री भी सस्ते दाम पर उपलब्ध हो रही है।

ई-निलामी प्रणाली और सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं से खनन गतिविधियों की जवाबदेही बढ़ी है, जबकि अवैध खनन पर सख्ती से नियंत्रण रखा गया है। केंद्र ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में उत्तराखंड की प्रगति की सराहना करते हुए बताया कि राज्य खनन सुधारों के मामले में नागालैंड और जम्मू-कश्मीर सहित अन्य राज्यों की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य अब उत्तराखंड की खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि खनन क्षेत्र अब राज्य के राजस्व और रोजगार का एक मजबूत स्रोत बन चुका है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पारदर्शिता, समयबद्धता और पर्यावरण संरक्षण के साथ सुधारों को लगातार आगे बढ़ाया जाए, ताकि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय और मॉडल राज्य के रूप में स्थापित हो।